खण्ड–25, अंक–01
मंगलवार, 05 फाल्गुन, शक संवत्, 1930
(24 फरवरी, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 25 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
राष्ट्रगीत	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	1-17
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश	17-18

‘क’

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डेय
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती आशा
5–श्री ओम गोपाल
6–श्री करन मेहरा
7–सुश्री कैरन मेयर
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोगा राम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–हाजी तस्लीम अहमद
24–श्री तिलक राज बेहड़
25–श्री दिनेश अग्रवाल
26–श्री दिवान सिंह
27–काजी मौ0 निजामुद्दीन
28–श्री प्रकाश पन्त
29–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
30–श्री प्रीतम सिंह
31–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
32–श्री प्रेमानन्द महाजन
33–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
34–श्री बलवीर सिंह नेगी
35–श्री बिशन सिंह चुफाल
36–श्री बृज मोहन कोटवाल
37–श्री भगत सिंह कोश्यारी
38–श्री मनोज तिवारी
39–श्री मयूख सिंह
40–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''
41–श्री मुन्ना सिंह चौहान
42–श्री यशपाल बेनाम
43–चौ0 यशवीर सिंह
44–श्री रणजीत रावत
45–डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
46–श्री राजकुमार
47–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
48–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
49–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
50–श्रीमती वीना महराना
51–श्री शहजाद
52–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
53–श्री सुरेन्द्र राकेश
54–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
55–डा0 हरक सिंह रावत
56–श्री हरभजन सिंह चीमा
57–श्री हरिदास

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में 03 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही राष्ट्रगीत ''वन्दे मातरम्'' से प्रारम्भ की जाती है।

राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शष्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थ ग्रहण करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

(श्री अध्यक्ष द्वार. श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ आरम्भ करते ही बहुजन समाज पार्टी के सभी मान ग सदस्य एवं भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय किशोर उप ाय, माननीय प्रीतम सिंह एवं माननीय रणजीत सिंह रावत को छोड़कर, सभी माननीय स. य 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

"उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय विधान सभा उपाध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा विधान सभा के माननीय सदस्यगण। सर्वप्रथम राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों का मैं अभिवादन करता हूँ और उत्तराखण्ड राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने हेतु सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

2–राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का गठन राज्य में चिन्हांकित कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित एवं अनुश्रवित किये जाने हेतु किया गया है। उक्त के अन्तर्गत "सरकार जनता के द्वार", "हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश" तथा "भयमुक्त समाज" की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए जन समस्याओं के प्रति प्रशासनिक मशीनरी को सकारात्मक रुख अपनाये जाने हेतु गतिमान किये जाने का संकल्प लिया गया है। विभिन्न संकल्पों में यह मूल भावना निहित है कि प्रदेश की ग्रामीण जनता को अपनी समस्याओं के लिये इधर–उधर न भटकना पड़े तथा उनकी समस्याओं का निराकरण स्थल पर ही कर दिया जाय। ऐसी समस्यायें, जिनका निराकरण स्थल पर सम्भव न हो, को भी एक समय सीमा के अन्तर्गत हल करते हुए जनता में एक नये आत्मविश्वास एवं स्फूर्ति को पल्लवित एवं विकसित किया जाय।

3–मेरी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पंचवर्षीय/वार्षिक/जिला योजनाओं की संरचना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर विशेष बल दे रही है ताकि समस्त प्रदेशवासियों के जीवन–स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो सके एवं राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों के समकक्ष लाया जा सके।

से
4–राज्य के अवस्थापना विकास को और अधिक गति देने के उद्दे किये
अतिरिक्त निवेश के लिए पी0पी0पी0 मोड में अधिकाधिक परियोजनाएं संचा को भी
जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजीनिवे
प्रोत्साहित किया जा रहा है।

की गुणवत्ता
[5–मेरी सरकार द्वारा कच्चे मार्गों को पक्का करने तथा पक्के मा हायता एशियन
में सुधार हेतु लगभग पांच सौ पचास मिलियन डॉलर की वित्तीय चरण में चौहत्तर
डेवलेपमेन्ट बैंक से प्राप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है तथा प्र तीय चरण के लिए
मिलियन डॉलर व पांच सौ छप्पन कि0मी0 के कार्य प्रगति पर हैं व कार्य हेतु निविदाएं
दो सौ मिलियन डॉलर एवं नौ सौ सड़सठ कि0मी0 मार्गों के सु
आमंत्रित की जा चुकी हैं।

ा–देहरादून मार्ग को चार
6–मेरी सरकार के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा दि के लिए निविदा की प्रक्रिया
लेन का बनाने की योजनान्तर्गत मुजफ्फरनगर–देहरादून मा रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु
प्रारम्भ कर दी गयी है तथा इस मार्ग पर लच्छीवाला प्रारम्भ किया जा रहा है। नई
धनराशि उपलब्ध करा दी है, जिसका कार्य शीघ्र नाने हेतु आठ लेन एक्सेस कंट्रोल्ड
दिल्ली–देहरादून के मध्य की यात्रा को और सुगम

एक्सप्रेस–वे निर्माण की परिकल्पना भी तैयार कर ली गई है, जिसे निकट भविष्य में पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित कराना प्रस्तावित है। राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत "अलमस–नगुण–भवान मोटर मार्ग" का निर्माण कार्य प्रगति में है। इस मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिला उत्तरकाशी से देहरादून की वर्तमान दूरी लगभग सत्तर कि0मी0 कम हो जायेगी।

7–आगामी सैफ खेलों के आयोजन हेतु राज्य अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत जिला देहरादून में स्वीकृत जौलीग्रांट–थानो–रायपुर चार लेन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य मेरी सरकार द्वारा शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है। जिला नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 54 में कोसी नदी पर रु0 19.52 करोड़ अनुमानित लागत के सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। मेरी सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों को समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पादित करने तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में गति लाने के निमित्त राज्य का अपना एक स्वायत्तशासी निगम **उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम** गठित किया जा चुका है।

मेरी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चार विशेषज्ञ संस्थाओं को चयनित किया गया है, जिनके माध्यम से रु0 5.00 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा। एक करोड़ से पाँच करोड़ रुपयों तक के कार्यों के लिए सेवानिवृत्त अभियन्ताओं का एक पैनल गठित किया गया है, जिनके माध्यम से उक्त कार्यों में भी निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

8–मेरी सरकार ने राज्य में पर्यटन को विकसित करने, औद्योगिक विकास के लिये राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने तथा आपदा राहत कार्यों में सुगमता के लिये विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है। इसी क्रम में जौलीग्रांट (देहरादून) हवाई अड्डे का विस्तार कर यहाँ से नियमित विमान सेवा आरम्भ की जा चुकी है। पन्तनगर हवाई पट्टी से विमानों के नियमित संचालन के लिए विस्तार कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा 25 स्थलों पर नये हैलीपैड्स के निर्माण की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और यह प्रयास है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक हैलीपैड का निर्माण किया जाय।

मेरी सरकार ने सार्वजनिक सेवायान से दुर्घटना होने पर मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को राहत राशि प्रदान किये जाने के लिए दुर्घटना राहत निधि के गठन हेतु **"उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि"** की स्थापना की है।

9–राज्य की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। मेरी सरकार जल स्रोतों के घटते स्राव से अत्यन्त चिन्तित

है एवं इसके दृष्टिगत जल स्रोतों के रखरखाव एवं संवर्द्धन हेतु प्रयास किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा विश्व बैंक सहायतित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा कार्य योजना–प्रथम चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु भी कार्यक्रम प्रस्तावित है।

10–मेरी सरकार द्वारा जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत गूल, हौज, हाईड्रम, आर्टीजन कूप, वियर एवं पम्पसैट का निर्माण कर लगभग सत्तर हजार हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन कर कृषकों की कृषि भूमि में उत्पादकता वृद्धि कर उनकी आय में वृद्धि का प्रयास किया गया है।

11–मेरी सरकार राज्य के असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से आच्छादित करने तथा आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु प्रयासरत है। जमरानी बांध परियोजना की डी0पी0आर0 को पुनरीक्षित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। सौंग बांध की डी0पी0आर0 तैयार हो चुकी है। मेरी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन पर कार्य कर रही है ताकि कम पानी से अधिक सिंचाई की जा सके।

मेरी सरकार द्वारा अल्मोड़ा में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु कोसी नदी पर बहुउद्देशीय बांध के निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। उत्तराखण्ड में नदियों एवं नालों की बाढ़ से हो रहे कृषि भूमि के कटाव एवं आबादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है।

मेरी सरकार जल स्तर की गिरावट रोके जाने के उद्देश्य से छोटी–छोटी नदियों एवं जल स्रोतों को जोड़कर छोटे जलाशय बनाने पर विचार कर रही है।

12–राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में लगभग 3140 मेगावाट क्षमता की परियोजनायें स्थापित की जा चुकी हैं तथा लगभग 13000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का विकास एवं निर्माण किया जा रहा है। आराकोट–त्यूनी तथा त्यूनी–प्लासू जल विद्युत परियोजनाओं की डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार कर भारत सरकार को भेजी जायेगी। भारत सरकार के माध्यम से 6000 मेगावाट की पंचेश्वर बांध परियोजना के कार्य आरम्भ करने हेतु भी मेरी सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किये गये हैं। मेरी सरकार का यह भी प्रयास है कि किशाऊ बांध परियोजना तथा लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मध्य सहमति बनाकर परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। इसके अतिरिक्त लम्बे समय से रुकी व्यासी जल विद्युत परियोजना पर पुनः कार्य आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

जनसहभागिता तथा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिये जाने के दृष्टिगत 25 मेगावाट क्षमता तक की स्वयं चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन का कार्य प्रगति पर है।

जनपद उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित 304 मेगावाट क्षमता की उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की मनेरी भाली द्वितीय जल विद्युत परियोजना द्वारा व्यावसायिक रूप से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। चार लघु जल विद्युत परियोजनाओं (कालीगंगा–प्रथम व द्वितीय, मदमहेश्वर व कालन्दीगाड़) में एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में आठ नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्मित किये जा चुके हैं एवं सोलह अन्य विद्युत उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्रह नये उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है।

राज्य में एकीकृत पारेषण तंत्र के विकास हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से योजना तैयार की गई है तथा दो परियोजनाओं–400 के0वी0 लोहारीनाग–पाला कोटेश्वर लाइन तथा 400/200 के0वी0 श्रीनगर सब–स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में ऋण अनुबन्ध पर विचार–विमर्श अन्तिम चरण में है तथा इसी वित्तीय वर्ष में ऋण अनुबन्ध सम्भावित है।

मेरी सरकार द्वारा विगत महीनों में, जबकि प्रदेश में जल–विद्युत उत्पादन में कमी आती है, मुख्यतः सुनियोजित बैंकिंग की व्यवस्था कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा पहली बार ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा को भी शामिल किया गया और रॉयल्टी से छूट दी गयी।

13–मेरी सरकार द्वारा वनों में औषधीय पौधों की वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिये वैज्ञानिक तरीके से रेपिड मैपिंग एक्सरसाइज की जा रही है तथा इनकी उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विकास किया जा रहा है।

- अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में वन्य जीव पुनर्वास केन्द्र की स्थापना आरम्भ कर दी गयी है।
- वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय ग्राम–समितियों का गठन किया गया है, जिनमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
- बांस, रिंगाल, बायोफ्यूल, च्यूरा, थुनेर, त्रिफला एवं अन्य औषधीय प्रजातियों का रोपण करके स्वरोजगार के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं।
- जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ईकोटूरिज्म हेतु वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थनों का विकास किया जा रहा है।

वर्तमान में विश्व बैंक की सहायता से लगभग चार सौ करोड़ रुपये की लागत की उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत पर्वतीय जिलों के अठ्ठारह विकास खण्डों में ग्रामीण समुदाय के सदस्यों की क्षमता एवं कौशल–विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों व कार्यशालाओं के साथ ही जीविकोपार्जन के अवसरों में वृद्धि के कार्यक्रमों एवं जलागम विकास प्रबन्धन के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

14–मेरी सरकार द्वारा राज्य के लिए ई–गवर्नेन्स रोड मैप (इ0जी0आर0एम0) का निर्धारण कर लिया गया है। उत्तराखण्ड स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर एवं कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना तथा विभिन्न विभागों हेतु एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ जनता तक पहुँचाने तथा राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु इसका उपयोग प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किये जाने हेतु मेरी सरकार प्रयासरत है।

15–मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ उद्योगों की संख्या लगभग नगण्य है, पूँजीनिवेश आकर्षित करने एवं इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कर आर्थिक विकास के उद्देश्य से उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष सुविधाएं विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अन्तर्गत प्रदान की गयी हैं। इससे जनशक्ति के पलायन पर रोक लगेगी। साथ ही, औद्योगिक पैकेज की अवधि बढ़ाने के लिए भी मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के स्तर पर निरन्तर प्रयास किये गये हैं। मेरी सरकार हथकरघा योजनाओं को भी कारगर रूप से संचालित कर रही है।

16–मेरी सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान योजना संचालित कर रही है। बस्ती के एक कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक/शिक्षा गारन्टी केन्द्र अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है। समस्त परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

17–मेरी सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिए कक्षा–नौ में प्रवेश पर एक हजार तथा कक्ष–दस में प्रवेश पर दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जा रही है तथा राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर 03 से 08 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। पच्चीस राजकीय इण्टर कॉलेजों को "स्मार्ट स्कूल" के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें विद्यालयों को कम्प्यूटर सहायक एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। मेरी सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु पृथक से

संस्कृत शिक्षा विभाग गठित किया गया है।

मेरी सरकार पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अपेक्षानुसार स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। 06 पॉलिटेक्निकों में द्वितीय शिफ्ट की कक्षायें संचालित की जा रही हैं। प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पन्तनगर में बी0टेक0 पाठ्यक्रम की लगभग एक सौ सीटों की वृद्धि की गयी है। उक्त के साथ ही दो नये पाठ्यक्रम–भूकम्प अभियांत्रिकी एवं इन्ट्रोडक्शन टू इन्वायरमैन्ट इन्जीनियरिंग आरम्भ किये जा रहे हैं।

18–युवा कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरी सरकार द्वारा लगभग दो हजार प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में मांग के आधार पर योजित करते हुए प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

19–मेरी सरकार ने–

- उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा इसे रोजगारपरक बनाते हुए जनमानस तक पहुँचाने हेतु निरन्तर कार्य किया है।
- 15 राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 कक्षाएं प्रारम्भ की गई हैं। राजकीय महाविद्यालयों में ईको टूरिज्म, पत्रकारिता, एल0एल0बी0, एम0बी0ए0 जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया है। महाविद्यालयों के लिए भवन, पुस्तकालयों, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए उप–योजनाओं हेतु धन उपलब्ध कराया गया है। हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दून विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में तीव्रता लाने का प्रयास कर रही है।
- राज्य में भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई0आई0एम0) की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

20–मेरी सरकार द्वारा समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा–परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि का सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से तीनों स्तरों पर संचालन किया जा रहा है। एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष पद्धति की सेवायें भी उपलब्ध कराने के लिये दोनों विभागों में समन्वय स्थापित कर चिकित्सा सेवा में सुधार किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा **पं0 दीनदयाल उपाध्याय देव भूमि 108 सेवा** प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत 90 एम्बुलेन्स वाहनों के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल आपात

स्थिति में चिकित्सालय तक पहुँचाया जाता है। यह सेवा प्रदेश के समस्त नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा के कार्य में उत्तराखण्ड उत्तर भारत का अग्रणी राज्य है।

श्रीनगर (गढ़वाल) में 380 शैय्याओं वाले **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज** की स्थापना कर उसे कार्यशील किया गया है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ–चिकित्सा का लाभ मिलेगा एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को चिकित्सा–शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त होंगे।

वर्तमान में राज्य के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत निजी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा/निदान केन्द्र स्थापित करने हेतु मेरी सरकार द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन दिया जायेगा।

21–मेरी सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेन्स योजना तथा बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर योजना के अधीन चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में मलिन बस्तियों में बेहतर आवास/समेकित विकास/जल आपूर्ति–सफाई सुविधा सहित बुनियादी सुविधाओं का प्राविधान किया जा रहा है।

- उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित तीन मिशन शहरों–देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में मलिन बस्ती सुधार, जलापूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन जैसी विभिन्न नागरिक सुविधाओं के सम्बन्ध में लगभग 170 करोड़ रुपये लागत की योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
- एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अन्य शहरों की मलिन बस्तियों में बेहतर आवास एवं समेकित विकास सहित बुनियादी सुविधाओं का प्राविधान किया जा रहा है।
- छोटे एवं मध्यम श्रेणी के शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरातत्व क्षेत्रों का विकास आदि का कार्य भी किया जा रहा है।
- नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत मोहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (ए0डी0बी0 सहायतित) के प्रथम ट्रांच में सम्मिलित तीन शहरों देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल में वाटर सप्लाई तथा सीवरेज आदि के विकास के लिए स्वीकृत साठ मिलियन डालर ऋण के लिए ए0डी0बी0 तथा भारत सरकार/राज्य सरकार के मध्य ऋण अनुबन्ध सम्पन्न हो चुका है। इस दिशा में मेरी सरकार सक्रियता से अग्रेत्तर कार्य सम्पादित कर रही है।

हरिद्वार में वर्ष 2010 में कुम्भ मेले के सफल आयोजन के लिए मेरी सरकार द्वारा अवस्थापना विकास एवं प्रबन्धन हेतु समयबद्ध एवं नियोजित ढंग से कार्यवाही की जा रही है।

- देहरादून के सुनियोजित विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु महायोजना वर्ष 2005–2025 घोषित कर दी गयी है तथा हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना वर्ष 2005–2025 को शीघ्र घोषित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रचलित विभिन्न अधिनियमों में उपबन्धित व्यवस्थाओं को समाहित कर उत्तराखण्ड नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- टिहरी झील क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

22–उत्तराखण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगारपरक बहुमुखी विधाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित विकास करते हुए पर्यटन को प्रदेश की आर्थिक व सामाजिक विकास की धुरी के रूप में स्थापित करने हेतु मेरी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। मेरी सरकार हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि की रेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट का विकास भारत सरकार के सहयोग से कर रही है।

- जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी के सहयोग से राज्य के चारों धामों (यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ) तथा उक्त धामों के मार्गों में पड़ने वाले विभिन्न पर्यटक/तीर्थ स्थलों यथा–फूलों की घाटी, गोविन्दघाट, घांघरिया, हेमकुण्ड साहिब, माणा, औली आदि को विकसित करने के लिये दीर्घकालीन पर्यटन विकास की योजना के अन्तर्गत मेरी सरकार ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है।
- मेरी सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना माह–जून, 2008 से प्रारम्भ की है।

मेरी सरकार के अथक प्रयासों से वर्ष 2009 में प्रथम सैफ विन्टर गेम्स आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

23–भारत का संविधान के अनुच्छेद 351 एवं आठवीं अनुसूची में वर्णित भारतीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हेतु भाषा संस्थान के गठन की कार्यवाही गतिमान है। भाषा संस्थान के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अन्य भारतीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हेतु मेरी सरकार कृतसंकल्प है।

उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय बोलियों यथा गढ़वाली एवं कुमाऊँनी बोलियों के विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु मेरी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

24–मेरी सरकार ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है।

25–मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्वच्छकारों एवं समाज के सभी शोषित और कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही है। उनकी आय में वृद्धि एवं जीवन–स्तर में उन्नयन हेतु अनेकानेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

समाज के उपेक्षित वर्गों के उत्थान हेतु मेरी सरकार द्वारा **राज्य सफाई कर्मचारी आयोग** का गठन किया गया है।

अल्पसंख्यक भाईयों एवं बहनों की ओर मेरी सरकार का विशेष ध्यान है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही की जा रही है।

मेरी सरकार निराश्रित विधवाओं, विकलांगों एवं वृद्धजनों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन तथा छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सरलीकृत तथा पारदर्शी बनाने हेतु मेरी सरकार द्वारा लाभार्थियों को बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खातों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

26–भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों तथा उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाओं को उपलब्ध कराना पुनर्वास तथा पुनर्नियोजन कराना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

मेरी सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर की पेंशन/अनुदान एक हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है, और–

- 01 अप्रैल, 2004 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के पंजीकरण पर लगाया हुआ प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।
- उत्तराखण्ड पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान को पाँच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष दस लाख रुपये दिये जा रहे हैं।
- वीरता पदक पर देय अनुदान में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी के साथ–साथ निम्न संशोधन भी किये गये हैं :–

  (अ) वार्षिकी, तीस वर्ष के स्थान पर जीवनकाल तक अनुमन्य;

  (ब) सैनिक विधवाओं को भी वही दर आजीवन अनुमन्य;

  (स) वीरता पदक से अलंकृत आम नागरिकों व अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों को भी वही दरें अनुमन्य।

मेरी सरकार ने ईको टाक्स फोर्स की चार अतिरिक्त कम्पनी का गठन किया है जिससे न केवल राज्य के पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि लगभग चार सौ पूर्व सैनिकों को रोजगार भी मिलेगा।

27—मेरी सरकार लगभग नौ हजार आंगनबाड़ी केन्द्र एवं दो हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, महिलाओं (गर्भवती, धात्री, किशोरियों) को अपेक्षित सेवायें प्रदान कर रही है।

मेरी सरकार—

- पका—पकाया भोजन तैयार करने हेतु माता समितियों का गठन कर महिलाओं को प्रबन्धन में भागीदार बना चुकी है।
- किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग उनतीस हजार किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, आत्मनिर्भर बनाने एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया गया है।
- बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत लगभग बयालीस हजार बालिकाओं के नाम से एन0एस0सी0 बनाई गई है।
- प्रदेश में लिंग अनुपात में आ रहे अन्तर को कम करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, कन्या शिशुओं को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से बराबरी के स्तर पर लाने के उद्देश्य से **"नन्दा देवी कन्या योजना"** आरम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार में कन्या जन्म के उपरान्त बालिका के पक्ष में माता के संरक्षण में एकमुश्त रु0 5000/— की दीर्घावधिक सावधि जमाराशि प्रदान की जायेगी, जो कन्या की आयु 18 वर्ष पूर्ण करने तथा छात्रा के रूप में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त बालिका के हित में उपयोग की जा सकेगी।
- **स्वयंसिद्धा परियोजना** के अन्तर्गत राज्य में 1100 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया है।
- कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिये जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर माता—पिता को कुपोषण रोग के प्रति जागरुक कर रही है।

28—राज्य की अधिकांश जनता कृषि सम्बन्धी कार्यों से जुड़ी हुई है, किन्तु अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित हैं, जिसके फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों, जैसे जल, जमीन तथा वनों के सुनियोजित उपयोग व प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाए जाने की दिशा में मेरी सरकार ने ठोस कार्यवाही किए जाने का संकल्प लिया है।

- वर्तमान वर्ष में लगभग पांच लाख कुन्तल विधायनित, प्रमाणित एवं आधारीय बीज का उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराया गया है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमाणित बीज उत्पादन क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ बीज परीक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए कृषक मेले एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों में प्रतिभागिता कर उत्तराखण्ड को बीज एवं जैविक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास जारी हैं।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा अत्याधुनिक विषयों, जैसे प्रीसीजन एग्रोनॉमी, भूकम्प अभियांत्रिकी तथा पर्यावरण प्रौद्योगिकी पर नये कोर्स विकसित किये गये हैं, जबकि नैनो टैक्नोलॉजी, बायोइन्फार्मेटिक्स, पोस्ट हार्वेस्ट, फिजियोलॉजी, पर्यावरणीय आर्थिकी व जलवायु परिवर्तन आदि पर नये पाठ्यक्रम विकसित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय फार्म का आधुनिकीकरण तथा मटकोटा स्थित कार्यशाला को अत्याधुनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है।

29—राज्य में उच्चकोटि की रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से तथा बागानों की समग्र उत्पादकता बढ़ाये जाने के दृष्टिगत प्रचलित नई किस्मों/प्रजातियों को बौने किस्म के मूलवृन्तों पर अमेरिका, नीदरलैण्ड, थाईलैण्ड तथा अन्य देशों एवं राज्यों से आयात कर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

- स्थापित उद्यान सचल दल केन्द्रों में से इस वर्ष छब्बीस (26) उद्यान सचल दल केन्द्रों का चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ीकरण किया है तथा सड़सठ (67) राजकीय उद्यानों को विकसित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
- मेरी सरकार द्वारा मौसम आधारित **सेव बीमा योजना** का लाभ कृषकों को दिया जा रहा है।
- राज्य में उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा लगभग 549 हेक्टेयर में चाय बागान स्थापित कर रखरखाव किया जा रहा है तथा 220 हेक्टेयर क्षेत्र से जैविक चाय तैयार कर उसे उत्तराखण्ड टी के नाम से बिक्री की गयी है।
- वन्य रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु व्यापक आधार युक्त स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया गया है।
- रेशम उत्पादन में वृद्धि हेतु प्राथमिक रेशम सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ किया गया है।
- पंजीकृत काश्तकारों द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटी की निकासी की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है तथा राज्य औषधि पादप बोर्ड एवं जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है, ताकि जड़ी-बूटी, औषधीय पादपों के कृषिकरण एवं संवर्द्धन को बढ़ावा मिल सके। कृषिकरण से प्राप्त सुगंध पादपों के विपणन में कृषकों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पचास लाख रुपये का रिवाल्विंग फण्ड सृजित किया गया है।

30—गन्ना किसानों के लम्बित देयकों के भुगतान के लिए रु0 56 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी।

31—मेरी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि प्रदेश में पशु सम्पदा व कुक्कुट सम्पदा का विकास इस दृष्टि से किया जाय कि उनकी उत्पादक क्षमता में अभिवृद्धि हो, जिससे पशुपालन को व्यवसाय के रूप में चला रहे निर्बल लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। बटेर के व्यावसायिक उत्पादन का कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है।

32—डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा नगरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों एवं अन्य संस्थानों में उत्तम गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये मेरी सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से डेरी विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है। चीज़ उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मेरी सरकार द्वारा सार्थक पहल की गयी है।

33—मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहन दिये जाने एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध किये जाने हेतु मत्स्य पालक विकास अभिकरण एवं शीत जल मात्स्यिकी तथा जलजीव पालन योजना संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

34—मेरी सरकार के प्रयासों से—

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगारियों तथा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के समूहों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराकर अब तक लगभग बयालीस हजार (42,000) स्वरोजगारियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है।
- राज्य के पांच जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के सत्रह विकास खण्डों के गरीबतम तैंतालिस हजार परिवारों की आजीविका संवर्द्धन हेतु **"हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना"** संचालित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना टिहरी, चम्पावत एवं चमोली जिलों में प्रारम्भ थी तथा अब इस योजना को शेष जिलों में भी आरम्भ कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत लगभग आठ लाख परिवारों को जॉब कार्ड वितरित किये गये तथा एक लाख श्रमिक परिवारों द्वारा रोजगार हेतु आवेदन किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाकर रु0 100/— प्रतिदिन निर्धारित की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा सुदूर क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवारों को अब तक लगभग पांच सौ (500) गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरित किये गये हैं।

35–मेरी सरकार द्वारा सहकारिता आन्दोलन को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा लिये जाने वाले सहकारी ऋणों पर ब्याज दरों पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सहकारिता सहभागिता योजना प्रारम्भ की गयी है।

36–मेरी सरकार ने पंचायत राज के लिए उपलब्ध धनराशि से नागरिक सेवायें, जैसे मार्ग–प्रकाश व्यवस्था का रखरखाव, नाली, सड़क एवं खड़ंजा निर्माण एवं जिला पंचायतों की पुरानी सम्पत्तियों की विशेष मरम्मत तथा नयी सम्पत्तियों के सृजन पर तत्परता से कार्यवाही की है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य के 12 जिलों में त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव सफलता पूर्वक सम्पन्न कराए गये।

37–मेरी सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारियों, जिलों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों में अर्द्ध न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से स्थापित उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला नैनीताल में प्रशिक्षण दिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

- जनता को सुलभ न्याय प्रदान किये जाने हेतु विकासनगर, जिला देहरादून एवं टनकपुर, जिला चम्पावत में सृजित सिविल जज (जू0डि0) न्यायालयों का संचालन प्रारम्भ हो गया है। विभिन्न स्तरों के 65 नये न्यायालयों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- हल्द्वानी, जिला नैनीताल में रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया जा चुका है।

38–मुम्बई की आतंकवादी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से जागरुक है तथा पुलिस व्यवस्था एवं अभिसूचना तन्त्र को सुदृढ़ किये जाने हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। मेरी सरकार द्वारा राज्य की पुलिस संचार व्यवस्थाओं में उत्तरोत्तर विकास, नेटवर्किंग, सुदृढ़ अभिसूचना तंत्र, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, यातायात नियंत्रण हेतु सर्विलांस सिस्टम को स्थापित किया गया है। साथ ही, प्रदेश में राज्य पुलिस बोर्ड एवं राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की भी स्थापना की गयी है, जोकि पुलिस की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने में सहयोगी होगा।

39–मेरी सरकार राज्य में वित्तीय अनुशासन कायम करते हुए विकास कार्यों को गति देने के लिये कटिबद्ध है। छठे वेतन आयोग के कारण अतिरिक्त व्यय भार पड़ने पर भी मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि राज्य सरकार आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि करे। विभिन्न विभागों तथा सेक्टरों से सम्बन्धित केन्द्रीय तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को सूचीबद्ध कर तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ विचार–विमर्श कर, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन योजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके।

मेरी सरकार द्वारा राज्य में ऋण–जमा अनुपात, जो माह जून, 2007 में 41.60 प्रतिशत था तथा माह जून, 2008 तक 43.72 प्रतिशत तक पहुँच गया है, को और बढ़ाने के लिये राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से विशेष प्रयास किये जायेंगे।

40–मेरी सरकार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को सेवायोजित करने, पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं उनको समुचित सम्मान दिये जाने के लिए कृतसंकल्प है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान किये जाने हेतु कार्पस फन्ड की स्थापना की जा रही है।

मेरी सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन, यात्रा सुविधा एवं अन्य अनुषांगिक सुविधायें प्रदान करने तथा राज्य के राजकीय समारोहों में विशेष रूप से सम्मानित एवं आमंत्रित किये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

41–राज्य के जनमानस की संवेदनशीलता से जुड़ते हुए मेरी सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अनुरूप राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, समस्त जिलों में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपदा निधि, जिला आपदा निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एवं जिला आपदा न्यूनीकरण निधियों की स्थापना की जा चुकी है तथा राज्य आपदा सलाहकार समिति का भी गठन किया जा चुका है।

42–उत्तराखण्ड में मधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्कृति विकसित करना, बाल/बंधुवा श्रम की सामाजिक बुराई की रोकथाम की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करना, महिला श्रमिकों को शोषण से बचाना, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, संगठित/असंगठित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एवं श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनायें तैयार कर उन्हें कार्यान्वयन करना आदि मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

43–मेरी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिये कटिबद्ध है और इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है।

44–मेरी सरकार ने जनता से सीधे समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास कार्यों के निर्धारण, संचालन एवं क्रियान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। अतः मीडिया से प्रभावी संवाद एवं समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारों के कल्याण के प्रति मेरी सरकार पूरी तरह से सजग एवं प्रयत्नशील है। इसी उद्देश्य से पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके परिजनों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'कारपस फण्ड' की व्यवस्था की गई है।

मेरी सरकार द्वारा दूरदर्शन के डी0डी0–1 पर साप्ताहिक न्यूज मैगजीन, 'उत्तराखण्ड दर्शन' के प्रसारण की व्यवस्था की गई है।

पत्रकारों से बेहतर समन्वय एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु **मीडिया सलाहकार समिति** का गठन किया गया है।

45–सरकारी मशीनरी को जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से संकल्प लिया गया है कि सरकारी अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों का नियमित निरीक्षण करेंगे तथा जन शिकायतों को सुनने एवं उनके निस्तारण के लिये प्रत्येक कार्यालय में समय सीमा निर्धारित करेंगे। जनता की शिकायतों का निराकरण तो किया ही जायेगा साथ ही जन शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायत करने वाले याची को भी उसके द्वारा की गई शिकायत में हुई कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को स्थापित करना है।

मेरी सरकार द्वारा–

- राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरने की कार्यवाही की जा रही है।
- सेना में वीरगति पाये सैनिकों के परिवार के सदस्यों को राज्याधीन समूह 'ग' व समूह 'घ' की सेवाओं में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है।
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, निष्पक्ष, शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी बनाये जाने तथा साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त किये जाने हेतु पूर्व के समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए नई व्यवस्था की गई है।
- मेरी सरकार स्वच्छ एवं जवाबदेह प्रशासन बनाने के लिए कटिबद्ध है। मेरी सरकार ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए सतर्कता अधिष्ठान को और अधिक सुदृढ़ किया है। लोकायुक्त संगठन को भी और अधिक सुदृढ़ किये जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

46–मेरी सरकार के प्रयास से अब तक 104 विभाग/संवर्ग के कार्मिकों के अन्तिम आवंटन की कार्यवाही हो चुकी है तथा सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण हेतु भी पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

47–मेरी सरकार ने वित्तीय अनुशासन और मितव्ययता को लागू करते हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रभावी पहल की है। जहाँ एक ओर सरकार ने राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान छठे वेतन आयोग का लाभ अनुमन्य कराया है, वहीं दूसरी

और विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया है। मेरी सरकार का यह भी प्रयास है कि वर्तमान विश्वव्यापी मन्दी के दौर में ऐसे कार्यक्रम संचालित किये जायं जिनसे आर्थिक मन्दी का प्रभाव प्रदेशवासियों पर कम से कम पड़े तथा विकास की दर भी प्रभावित न हो।]

.... मैंने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा है। मुझे आशा है कि आप सभी सदस्यगण लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए सदन में राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देंगे तथा आपसी सहयोग और सामंजस्य से राज्य की समस्याओं का समाधान ढूँढने की दिशा में सफल होंगे। मैं माननीय सदस्यगणों का आभार व्यक्त करते हुए वित्तीय और अन्य विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ।''

जय हिन्द।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2009 की बैठक में दिनांक 24 तथा 25 फरवरी, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

फरवरी, 2009

24 मंगलवार	माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ। (03:00 बजे, अपराह्न)
25 बुधवार	1–औपचारिक कार्य। 2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा चर्चा। 3–वित्तीय वर्ष 2009–2010 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण। (04:00 बजे, अपराह्न)

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–**

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

देहरादून,
दिनांक : 24 फरवरी, 2009

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधान सभा / 399–29–12–2010–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।